उपर्युक्त सभी संविदाओं पर हस्ताक्षण कर लिए गए हैं। विदेशी कंपनियों द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने का अनुमान है।

संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के अंतर्गत 8 मध्यम आकार के क्षेत्रों का दूसरा प्रस्ताव अक्तूबर, 1993 में किया गया। 7 मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए 34 बोलियां प्राप्त हुईं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत 28 अन्वेषण ब्लाकों का एक और प्रस्ताव 1995 में किया गया। 7 ब्लाकों के लिए 22 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह सरकार के विचाराधीन हैं।

Policy for grant of fishing permits

229. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the present policy of Government with regard to grant of fishing permits;

(b) whether Government have cancelled all permits/lease granted to private individuals and also to joint sector on *fishing*;

(c) the financial implication of the present and revised deep sea fishing policy; and

(d) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) The New Deep Sea Fishing Policy 1991, includes shcemes for Joint Venture, Leasing and Test Fishing for operation of deep sea fishing vessels in the Indian Exclusive Economic Zone. Apart from this, chartering of foreign vessels was allowed under charter policies of 1981 and 1986, which have been phased out and permits are being issued only in respect of the cases where it is legally warranted to grant the same.

(b) No, Sir. However, a committee constituted for making recommendations for the review of deep sea fishing policy has submitted its report on 8th February, 1996. Action has been initiated at inter-Ministerial level to examine the recommendations of this Review Committee.

(c) and (d) As the deep sea fishing policy has not been revised, the question of financial implication in case of its revision does not arise at present.

पुलिस के काम-काज के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए विधिक निकाय की स्थापना

230. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुलिस के काम-काज के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए एक विधिक निकाय की स्थापना करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Collaboration with American companies in food processing industries

231. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian and American companies have decided to develop greater collaboration in the food processing industry;

(b) whether Government have granted permission for the collaboration of the Indian companies with the American companies; and